हरिभूमि
विराट भूमि
शहडोल | बुढ़ार | धनपुरी | ब्यौहारी | जयसिंहनगर | बाणसागर
जबलपुर, शुक्रवार 19 जून 2026
login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

ब्यौहारी-गोहपारू-सिंहपुर में क्षमता से अधिक बच्चों को किया भर्ती

शहडोल। जिले में नौनिहालों को लील रहे कुपोषण के खिलाफ दावों की पोल खुल चुकी है। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी के बीच जमीनी हकीकत यह है कि जिले के पोषण पुनर्वास केंद्र कहीं ओवरलोड से हांफ रहे हैं, तो कहीं बदइंतजामी के कारण बेड खाली पड़े हैं। जिले के कुल 70 बेडों में से 66 पर मासूम भर्ती हैं, लेकिन सेंटर्स के बीच का असंतुलन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मिसमैनेजमेंट का सबसे वीभत्स रूप ब्यौहारी और गोहपारू में देखने को मिल रहा है। ब्यौहारी एनआरसी में क्षमता महज 10 बेड की है, लेकिन वहां 14 तड़पते मासूमों को ठूंस दिया गया है। यानी क्षमता से 4 बच्चे ज्यादा, यही हाल गोहपारू का है, जहां 10 बेड पर 13 बच्चे और सिंहपुर में 10 बेड की क्षमता के मुकाबले 12 बच्चों का इलाज रेंग रहा है। इन केंद्रों में पैर रखने की जगह नहीं है, स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ है और व्यवस्थाएं दम तोड़ रही हैं। इसके ठीक उलट, जिला चिकित्सालय शहडोल का हाल देखिए। जहां सबसे बेहतरीन सुविधाएं होनी चाहिए, वहां 20 बेड की क्षमता होने के बावजूद महज 9 बच्चे भर्ती हैं और 11 बेड खाली सफेद हाथी बने हुए हैं। क्या जिला मुख्यालय के आस-पास कुपोषण खत्म हो गया है या फिर मैदानी अमला गंभीर बच्चों को यहां तक लाने में नाकाम साबित हो रहा है। जयसिंहनगर और बुढ़ार के एनआरसी केंद्रों में भी स्थिति तंग है। दोनों ही केंद्रों में 10-10 बेड की क्षमता के मुकाबले 9-9 बच्चे भर्ती हैं और महज 1-1 बेड ही खाली बचा है। विभाग भले ही कागजी घोड़े दौड़ाकर ऑल इज वेल का राग अलापे और पौष्टिक आहार व चिकित्सकीय देखरेख के बड़े-बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक फील्ड स्टाफ गांवों से कुपोषित बच्चों को सही एनआरसी केंद्र तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक यह असंतुलन मासूमों की जान लेता रहेगा। ब्यौहारी और गोहपारू के केंद्रों पर मंडरा रहा अतिरिक्त भार और जिला अस्पताल की खाली सीटें सिस्टम की नाकामी बयां कर रही हैं।

पात्रता परीक्षा से छूट के लिए सौंपा ज्ञापन

शहडोल। शिक्षकों के सम्मान और जायज हक की मांग को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने जिला मुख्यालय में हुंकार भरी। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के देशव्यापी आह्वान पर शहडोल जिले के कोने-कोने से जुटे लगभग 600 से अधिक आक्रोशित शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। शिक्षकों ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, सरकार को मानसून सत्र में विधेयक लाकर उनकी मांगें पूरी करनी ही होंगी। कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को भेजे गए इस तीखे ज्ञापन में केवल एक सूत्रीय मांग गूंजी वर्ष 2010 तक नियुक्त सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से पूर्णतः छूट प्रदान की जाए। सडक़ों पर उतरे प्रांतीय, संभागीय और ब्लॉक स्तर के शिक्षक नेताओं ने दोटूक कहा कि सालों से शिक्षा व्यवस्था को अपने खून-पसीने से सींचने वाले अनुभवी शिक्षकों पर परीक्षा थोपना उनका मानसिक उत्पीडऩ है। यदि आगामी मानसून सत्र में सरकार इस बाबत कानून बनाकर राहत नहीं देती, तो यह आंदोलन और उग्र रूप अख्तियार करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

पुलिस ने बिना बताए फूंक दिया शव, परिजनों का संगीन आरोप

शहडोल। कोतवाली पुलिस की संवेदनहीनता और संदेहास्पद कार्यप्रणाली ने खाकी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। शहर के वार्ड नंबर 12 से गुमशुदा हुए 54 वर्षीय रमेश सराफ की मौत के मामले में पुलिस के रवैये से आक्रोशित परिजनों ने सीधे आईजी और एसपी से लिखित शिकायत कर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। परिजनों का सीधा सवाल है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, तो मुडऩा नदी के पास मिले शव को लावारिस बताकर इतनी आनन-फानन में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया, क्या पुलिस किसी बड़ी साजिश पर पर्दा डालना चाहती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ रमेश सराफ बीते 6 जून को घर से निकले थे। परिजनों ने 7 जून को ही कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जबकि 8 जून को ही मुडऩा नदी के पास रमेश की लाश मिल चुकी थी।

साहब नहीं आए तो श्वान राज को सौंपा 13 सूत्रीय मांगों का पुलिंदा

ब्यौहारी में बेलगाम हुक्मरानों को कांग्रेस ने दिखाया आईना

शहडोल।

लोकतंत्र और चुनी हुई व्यवस्था का इससे क्रूर मजाक आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ब्यौहारी नगर परिषद में नाक तक डूबे भ्रष्टाचार और जनता की त्राहि-त्राहि मचाती बुनियादी समस्याओं के खिलाफ जब जनआक्रोश सडक़ों पर उतरा, तो जनता के टैक्स पर ऐश करने वाली अफसरशाही कूटनीतिक एसी कमरों में दुबक गई। कडक़ड़ाती धूप में घंटों नारे लगाने के बाद भी जब अहंकार में डूबे तहसीलदार या किसी सक्षम अधिकारी ने ज्ञापन लेने अपनी कुर्सी से उठने की जहमत नहीं उठाई, तो भडक़ी कांग्रेस ने जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र को ऐसा करारा और ऐतिहासिक थप्पड़ मारा है, जिसकी गूंज पूरे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में गूंज रही है। अधिकारियों की इस घोर संवेदनहीनता से बिफरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य कसते हुए एक आवारा कुत्ते को ही प्रतीकात्मक रूप से अपना 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंप दिया! अब ब्यौहारी की सडक़ों पर घूमता वह बेजुबान श्वान, इस गूंगे-बहरे प्रशासनिक तंत्र का असली चेहरा बन चुका है।

जब कुंभकर्णी नींद में सो गया ब्यौहारी का अमला

घटनाक्रम के मुताबिक, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यौहारी के बैनर तले नगर परिषद क्षेत्र में फैले घोटालों, अंधेरगर्दी और जनसमस्याओं के खिलाफ एक विशाल आमसभा और उग्र विरोध प्रदर्शन का शंखनाद किया गया था। सैकड़ों की तादाद में आक्रोशित जनता और कांग्रेसी जब गगनभेदी नारे लगाते हुए रैली की शक्ल में नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, तो वहां का सन्नाटा प्रशासन की नीयत बयां कर रहा था। जनता की फरियाद सुनना तो दूर, न तो इलाके के तहसीलदार मौके पर मौजूद थे और न ही जनता के पैसों से मोटी तनख्वाह उठाने वाला कोई दूसरा जिम्मेदार अफसर। घंटों इंतजार के बाद जब किसी साहब का दीदार नहीं हुआ, तो कांग्रेसी नेताओं का धैर्य जवाब दे गया। कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के मुख्य गेट के सामने ही बीच सडक़ पर डेरा डाल दिया और चक्काजाम कर दिया। इस दौरान जिला प्रशासन मुर्दाबाद और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों से पूरा ब्यौहारी गूंज उठा। कांग्रेसी नेताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ब्यौहारी की अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है, उसे न तो जनता की तकलीफों से कोई सरोकार है और न ही वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को तैयार है।

तो यह कुत्ता ही हमारा खेवनहार है...

धरने पर बैठे कांग्रेसियों ने अपनी कडक़ती आवाज में प्रशासन को आखिरी अल्टीमेटम दिया था कि अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी तय समय सीमा में उनका दर्द सुनने नहीं आया, तो वे मान लेंगे कि इस शहर की व्यवस्था इंसानों के नहीं, बल्कि जानवरों के भरोसे चल रही है। अहंकार में चूर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस चेतावनी को भी मजाक में उड़ा दिया। आखिरकार, सब्र का बांध टूटते ही कांग्रेसियों ने प्रशासनिक व्यवस्था की अर्थी पर व्यंग्य का कफन ओढ़ाते हुए वहां घूम रहे एक आवारा कुत्ते को पकड़ा। इसके बाद पूरे आदर और सम्मान के साथ उसे माला पहनाई गई और ब्यौहारी नगर परिषद के भ्रष्टाचार का काला चि_ा यानी 13 सूत्रीय मांगों की फाइल उस मूक बधिर श्वान के सुपुर्द कर दी गई। इस अभूतपूर्व और तीखे व्यंग्यात्मक प्रदर्शन को देखने के लिए मौके पर हजारों की भारी भीड़ जुट गई, जो प्रशासन की इस कुत्ता फजीहत पर जमकर ठहाके लगा रही थी और तालियां पीट रही थी।

अफसरशाही के इस अहंकार को मटियामेट करेगी जनता

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यौहारी के अध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी ने सीधे तौर पर सरकार और स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जनता की समस्याओं पर बात करने के लिए अधिकारियों के पास पांच मिनट का समय नहीं है। जब अफसरशाही इतनी अंधी हो जाए कि वह विपक्ष और जनता को कीड़े-मकौड़े समझने लगे, तो उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए यह कदम उठाना बेहद जरूरी था। अगर ब्यौहारी के साहबों को एसी कमरों से बाहर निकलने में डर लगता है, तो अब से हम अपनी हर शिकायत इस श्वान राज को ही सौंपेंगे, शायद इस बेजुबान में इन लापरवाह अधिकारियों से ज्यादा संवेदना बची हो।

राजनीतिक गलियारों में खलबली

ब्यौहारी में हुए इस उग्र और व्यंग्यात्मक आंदोलन ने साफ कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर विपक्ष अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। इस श्वान प्रदर्शन ने जिला प्रशासन की साख को पूरी तरह मटियामेट कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक, हर तरफ ब्यौहारी प्रशासन की चर्चा है। सवाल यह उठता है कि क्या जनप्रतिनिधियों और जनता को घंटों सडक़ पर तड़पाने वाले इन लापरवाह अधिकारियों पर कलेक्टर कोई सख्त हंटर चलाएंगे या फिर भ्रष्टाचार की इस लंका में अफसरशाही का यह खेल यूं ही बेखौफ जारी रहेगा? कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि यह सिर्फ शुरुआत है, अगर 13 मुद्दों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो अगली बार घेराव सीधे साहबों के बंगले का होगा।

रेलवे स्टेशन में यात्री का मोबाइल उड़ा ले गया उचक्का

शहडोल।

संभागीय मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के वीआईपी वेटिंग हॉल में शातिर चोरों ने सेंधमारी करते हुए एक यात्री का कीमती मोबाइल पार कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब यात्री मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर गहरी नींद में सो गया। हालांकि, चोर की यह करतूत स्टेशन पर लगे तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वह वारदात को अंजाम देकर सरपट भागता नजर आ रहा है। आरपीएफ ने फुटेज के आधार पर चोर की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, सिंहिनिया (उचेरा) निवासी 24 वर्षीय सुधीर गुप्ता, पिता शिवदयाल गुप्ता, ट्रेन नंबर 12854 से जबलपुर से शहडोल पहुंचे थे। रात लगभग 2:30 बजे वे स्टेशन के वेटिंग हॉल में अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर सो गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि एक संदिग्ध उचक्का काफी देर तक वेटिंग हॉल में यात्री बनकर बैठा रहा और सबको भांप रहा था। जैसे ही यात्री गहरी नींद में गया, शातिर ने बाहर निकलकर खिडक़ी से हाथ डाला और चार्जिंग पर लगा मोबाइल उड़ाकर रफूचक्कर हो गया। खास बात यह है कि रात में गश्त कर रहे आरपीएफ स्टाफ ने पीड़ित को 4-5 बार जगाकर सतर्क भी किया था, लेकिन लापरवाही के कारण यह वारदात हो गई।

चोरी की इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरपीएफ शहडोल ने मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रेस कर ली है और घेराबंदी तेज कर दी है। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्षेत्र की जनता और यात्रियों से इस शातिर चोर को पहचानने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी इस हुलिए के व्यक्ति को देखे, तो तत्काल आरपीएफ के शासकीय नंबरों पर सूचना दे, सूचनाकर्ता का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ ही आरपीएफ ने यात्रियों को सख्त हिदायत दी है कि यात्रा के दौरान बिल्कुल भी लापरवाह न बनें। रात के समय अपने कीमती सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पर्स और सूटकेस को अपनी सीधी निगरानी में रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही शातिर चोरों के लिए बड़ा मौका बन सकती है।

पूर्व सीएमओ दबा बैठीं 52 सरकारी फाइलें, अध्यक्ष ने लगाये आरोप

मैडम जाते-जाते ले गईं नपा की तिजोरी की चाबी

शहडोल।

नगर पालिका परिषद शहडोल भ्रष्टाचार, गुटबाजी और प्रशासनिक लापरवाही के बाद अब एक नए और बेहद चौंकाने वाले विवाद के दलदल में धंस गई है। नगर पालिका की कुर्सी छोड़ते ही तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) श्रीमती आशा मेढ़ा (भण्डारी) द्वारा कार्यालयीन कार्य की कुल 52 महत्वपूर्ण फाइलें (नस्तियां) अपने साथ ले जाने या दबाकर रखने का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस बड़े खेल के उजागर होने के बाद नगर पालिका से लेकर जिला प्रशासनिक गलियारों में हडक़ंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम दास जायसवाल ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है और फाइलों की रिकवरी के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है।

मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश के बाद 03 जून 2026 को नए सीएमओ निशांत सिंह ठाकुर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था और तत्कालीन सीएमओ आशा भण्डारी

को उसी दिन भारमुक्त (रिलीव) कर दिया गया था, लेकिन विदाई के साथ ही मैडम अस्पताल और विकास कार्यों से जुड़ी 52 सरकारी फाइलें भी अपने साथ समेट ले गईं। वर्तमान सीएमओ द्वारा 10 जून को वरिष्ठ कार्यालयों को इस संबंध में लिखित सूचना दी गई थी। यहां तक कि तत्कालीन सीएमओ को व्हाट्सएप के माध्यम से भी फाइलें वापस लौटाने का संदेश भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। सरकारी फाइलों को इस तरह दबाकर रखना सीधे तौर पर नियमों को ठेंगे पर रखना और शासकीय कार्य में जानबूझकर बाधा डालना है।लापता की गई इन 52 नस्तियों में कोई मामूली कागज नहीं, बल्कि शहडोल शहर के विकास की रीढ़ माने जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं। सोन बैराज निर्माणः इस महत्वपूर्ण परियोजना की निविदाएं पुनः अति शीघ्र आमंत्रित करने के निर्देश संचालनालय द्वारा दिए गए हैं, लेकिन फाइल गायब होने से टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह ठप है। लीगेसी वेस्ट और निर्माण कार्यः कचरा प्रबंधन और शहर के बड़े निर्माण कार्यों से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें भी नदारद हैं। वर्षा पूर्व आवश्यक तैयारियांः मानसून सिर पर है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण, जलभराव से निपटने की सामग्री क्रय करने और नालों की सफाई से जुड़ी नस्तियां गायब है।

नगर पालिका अध्यक्ष ने इस तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर शहडोल को पत्र सौंपकर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई और फाइलें वापस मंगाने के लिए आदेशित करने की मांग की है। इस पत्र की प्रतिलिपि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के भोपाल आयुक्त, संभाग शहडोल के कमिश्नर और संयुक्त संचालक को भी सादर सूचनार्थ भेजी जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर एक जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर रहीं अधिकारी ने इन 52 फाइलों को अपने पास क्यों रोक रखा है, इन फाइलों में ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसे सार्वजनिक होने या नए सीएमओ के हाथ लगने से बचाया जा रहा है।

इनका कहना है...

अति महत्वपूर्ण फाइलें प्राप्त न होने के कारण नगर पालिका के विभिन्न विकास कार्य और कार्यालयीन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है।

घनश्याम दास जायसवाल
अध्यक्ष नगर पालिका परिषद शहडोल

कांग्रेस-युवा कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निकाली अर्थी, शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका

शहडोल।

देश में लगातार हो रहे पेपर लीक, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख को लेकर आज धनपुरी नगर की सडक़ें राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो गईं। कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने संयुक्त रूप से मोर्चा खोलते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ अब तक का सबसे उग्र और आक्रामक प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ चुनाव आयोग की प्रतीकात्मक अर्थी निकालकर पूरे नगर में जुलूस निकाला, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर अपना तीखा विरोध दर्ज कराया।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ पर भडक़ा गुस्सा

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मंडलम कांग्रेस अध्यक्ष अनिल जायसवाल, युवा कांग्रेस नेता सैयद जुहैब और फैज़ खान ने सीधे तौर पर दिल्ली के हुक्मरानों को घेरा। नेताओं ने दहाड़ते हुए कहा कि देश का नौजवान सालों-साल खून-पसीना बहाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन मलाईदार पदों पर बैठे भ्रष्टाचारियों की शह पर पेपर लीक हो जाते हैं। सरकारी एजेंसियां परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में पूरी तरह नकारा साबित हुई हैं। युवाओं की उम्मीदों का कत्ल करने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।प्रदर्शनकारियों ने केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी करारा प्रहार किया। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज देश की आम जनता के मन में चुनावी पारदर्शिता को लेकर गहरी शंकाएं हैं। निष्पक्ष संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में लोकतंत्र बचाओ के नारों के साथ चुनाव आयोग की अर्थी निकाली गई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि संस्थाओं की स्वायत्तता और युवाओं के रोजगार से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ, तो यह चिंगारी आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर लेगी। इस बड़े सियासी शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद कलाम, संतोष सिंह सेंगर, इब्रार खान, राम सिंह दादा, आनंद मोहन जायसवाल, मुबारक मास्टर, अंकित सिंह, एस.पी. सिंह, कमलेश, शकील सिद्दीकी, रामसेजवन शर्मा, रामेश्वर गौतम, राजीव शर्मा, मोहम्मद साबिर, कुंज बिहारी द्विवेदी, रवि सिंह, बालो चौधरी, सलेमुद्दीन, शिवम सिंह, हर्ष पाठक और मनु गहरवार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं, युवा कांग्रेस की ओर से फैज़ल शेख, सनी ख़ान, सोनू चौबे, प्रथिमेश सिंह, इमरान ख़ान, आशु सिंह, रशीफ़ ख़ान, इकराम ख़ान, अनस ख़ान और अविश यादव सहित भारी संख्या में पहुंचे युवाओं ने गगनभेदी नारेबाजी से धनपुरी की सडक़ों को गुंजा दिया। धनपुरी में हुए इस उग्र प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि विपक्ष अब बैकफुट पर रहने के मूड में नहीं है और आने वाले दिनों में यह सियासी पारा और चढ़ेगा।

रंगमंच पर जीवंत हुआ महाभारत का महासंग्राम उरुभंगम के मंचन ने झकझोरी दर्शकों की रूह

खलनायक नहीं... महायोद्धा की तरह दिखा दुर्योधन

शहडोल।

11 दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव-2026 के दसवें दिन बुधवार को होटल शुभम पैलेस का सभागार तालियों की गडग़ड़ाहट और मानवीय संवेदनाओं के चरम से गूंज उठा। महाकवि भास रचित कालजयी नाटक 'उरुभंगम' के बेहद आक्रामक, धारदार और प्रभावशाली मंचन ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। शाश्वत उत्सर्ग यूथ थियेटर ग्रुप, धमतरी (छत्तीसगढ़) के कलाकारों ने इस महानाट्य को मंच पर इस कदर जीवंत किया कि उपस्थित जनसमुदाय भाव-विभोर हो उठा।

आमतौर पर खलनायक माना जाने वाला दुर्योधन इस नाटक में बिल्कुल अलग और मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत नजर आया। निर्देशक सोमनाथ साहू ने महाभारत की घिसी-पिटी रूढिय़ों को तोड़ते हुए दुर्योधन के चरित्र के उस पहलू को उजागर किया, जो अमूमन इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाता है। गदा युद्ध में भीम द्वारा अधर्म से उसकी जांघ तोड़े जाने के बाद, अपनी मृत्यु से ठीक पहले अतीत पर पश्चाताप करता और युद्ध की निरर्थकता को स्वीकार करता दुर्योधन हर किसी की आंखें नम कर गया।

नाटक की शुरुआत तीन सैनिकों के भयावह युद्धभूमि के सजीव वर्णन से हुई। मानसी यादव, काजल ध्रुव, गुंजा, चांदनी सेन, लीना, फालगुनी, लक्ष्मी, कोमेश्वरी और भूमिका साहू ने अपनी बेजोड़ संवाद अदायगी और ऊर्जस्वित अभिनय से दर्शकों को कुरुक्षेत्र के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। पुष्कर चंद्राकर और राहुल मंडावी के पाश्र्व संगीत की थाप ने दृश्यों में ऐसा रणघोष फूंका कि रोमांच चरम पर पहुंच गया।

सम्पूर्ण नाट्य एवं लोक कला समिति, शहडोल के इस अभूतपूर्व आयोजन के सूत्रधार लकी चतुर्वेदी ने बताया कि यह महोत्सव शहर के सांस्कृतिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। रित्विक दास मिश्रा के कुशल मंच संचालन में बढ़ रहे इस महोत्सव के अंतिम दिन आज आरम्भ थियेटर, भोपाल द्वारा बहुप्रतीक्षित नाटक 'फेयरवेल' का मंचन किया जाएगा।

खबर संक्षेप

ओवर लोड वाहनों के कारण सड़क पर आ गई बडी-बडी दरारें

कोतमा। विधानसभा क्षेत्र कोतमा अंतर्गत दारसागर तिराहा एवं भालूमाड़ा से चोलना-खूंटा टोला के बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में बारिश और भारी वाहनों के दबाव के कारण दरारें और बड़े गड्ढे बनने की घटनाएं हाल के वर्षों में मानसून के दौरान सामने आई थीं। इन दरारों के कारण अक्सर सड़क धंसने और सीमेंट उखड़ने से आवागमन मे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर लगातार भारी वाहनों के आवागमन के कारण सड़क के किनारे और बीच-बीच में दरारें और गहरे गड्ढे बन गए हैं। सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी समय-समय पर ग्रामीण आपत्ति जताते रहे हैं। दरारों और गड्ढों की वजह से बाइक सवारों और अन्य वाहनों के लिए दुर्घटना का खतरा बना रहता है। खूंटा टोला मार्ग पर जगह-जगह दरारें और बड़े गड्ढे होना एक गंभीर समस्या है। भारी वाहनों के आवागमन और लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जिससे अक्सर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और आवागमन बाधित होता है। यह सड़क मार्ग छत्तीसगढ़ सीमा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है और इस सड़क मार्ग में 24 घंटे वाहनों का आवागमन बना रहता है। जैतहरी मोजर बेयर प्लांट से राखड लोड कर बडे वाहनों का 24 घंटे आवागमन होने के कारण यह सड़क मार्ग की स्थिति ऐसी हो गई है। जबकि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग मे ओवर लोड वाहनों का आवागमन पूर्णतः वर्जित है। वावजूद इसके इस सड़क मार्ग से पावर प्लांट से राखड लोड कर भारी वाहनों का आवागमन निरंतर बना रहता है। ग्रामीण एवं वाहन चालकों ने इस सड़क की मरम्मत कार्य करवाये जाने की मांग की है।

ट्रैक्टर ने बाइक को मारी सीधी टक्कर, एक की मौत, दो जिंदगी और मौत के बीच

उमरिया। जिले के अमरपुर-चिल्हारी मार्ग पर रफ्तार के अंधाधुंध वीभत्स खेल ने एक और हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया। बेल्दी पड़वार मोड़ के पास तेज रफ्तार मौत बनकर दौड़े एक ट्रैक्टर ने सामने से आ रही बाइक को ऐसी जोरदार टक्कर मारी कि मौके पर ही चीख-पुकार मच गई। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले भीषण हादसे में बाइक चला रहे युवक के परखच्चे उड़ गए और उसने तड़प-तड़प कर मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, बाइक पर सवार दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।

आमने-सामने की भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, काल बनकर आ रहा ट्रैक्टर अमरपुर की ओर से आ रहा था, जबकि बाइक पर सवार तीन युवक चिल्हारी की तरफ बढ़ रहे थे। बेल्दी पड़वार के खूनी मोड़ पर दोनों वाहनों में इतनी भीषण टक्कर हुई कि बाइक के पुर्जे-पुर्जे हवा में उछल गए। दुर्घटना होते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने लहूलुहान घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरही पहुंचाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।

अंधा मोड़ या मौत का जाल

इस खूनी मोड़ को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त उबाल है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह मोड़ नहीं, बल्कि मौत का जाल बन चुका है। लोक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही के कारण यहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगा है और ना ही गति अवरोधक। नतीजतन, आए दिन यहां बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

मैहर के रहने वाले हैं युवक

अमरपुर पुलिस से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हताहत हुए युवक मैहर जिले के बदेरा क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर और उसके चालक को अमरपुर चौकी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस अब मामले की तहकीकात में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन बेलगाम रफ्तार के सौदागरों और सुस्त प्रशासनिक तंत्र पर कब नकेल कसी जाएगी।

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक संपन्न

उमरिया।

मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जनपरामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत जिला पंचायत सभागार, उमरिया में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य बुधपाल सिंह ने की।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए बुधपाल सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों से सुझाव प्राप्त कर एक व्यापक, व्यावहारिक एवं जनहितकारी नीति निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह विषय समाज के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आमजन, सामाजिक संस्थाओं, संगठनों तथा शासकीय एवं अशासकीय विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनके विचार, सुझाव एवं अभ्यावेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण नीति को लागू करने से पूर्व नागरिकों की राय प्राप्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। प्राप्त सुझावों एवं अभिमतों के आधार पर समिति अपनी अनुशंसाएं राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, लिव-इन रिलेशनशिप सहित विभिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक विषयों पर पडने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन विषयों से संबंधित लाभ, हानि, चुनौतियां, अवसर तथा पक्ष-विपक्ष के तर्कों के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर ने नागरिकों से अधिकाधिक सहभागिता करने का आग्रह करते हुए बताया कि इच्छुक नागरिक अपने सुझाव 22 जून तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। सभी सुझावों का समिति द्वारा गंभीरतापूर्वक संकलन किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, एसडीएम बांधवगढ़ अंबिकेश प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा, तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सोनी, डिप्टी कलेक्टर प्रत्युष श्रीवास्तव, आशुतोष अग्रवाल, त्रिभुवन प्रताप सिंह, पुष्पराज सिंह, राजेश शर्मा, अरुण त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

तीन दिनों से पानी की एक-एक बूंद को तरसे लहसुई कैंप के परिवार, पेयजल संकट के समाधान के लिए श्रमिक संगठनों और एसईसीएल प्रबंधन ने संभाला मोर्चा

कोतमा। एसईसीएल क्षेत्र अंतर्गत लहसुई कैंप में पिछले तीन दिनों से गहराए पेयजल संकट ने स्थानीय रहवासियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। भीषण गर्मी के बीच पानी की आपूर्ति ठप होने से श्रमिक परिवारों को दैनिक जरूरतों के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को दूर-दराज के स्थानों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए श्रमिक संगठनों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए एसईसीएल प्रबंधन से चर्चा की और समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई। श्रमिक नेताओं ने कहा कि पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता में लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और प्रभावित परिवारों को जल्द राहत मिलनी चाहिए। मामले की जानकारी मिलते ही एसईसीएल प्रबंधन के अधिकारी भी सक्रिय हुए और तकनीकी टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। जल आपूर्ति व्यवस्था में आई खराबी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया गया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति बहाल की जाएगी। श्रमिक संगठनों और प्रबंधन के संयुक्त प्रयास से प्रभावित क्षेत्र में वैकल्पिक जल व्यवस्था करने के साथ-साथ स्थायी समाधान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का समाधान जल्द होगा और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। लहसुई कैंप में उत्पन्न यह संकट एक बार फिर यह सोचने को मजबूर करता है कि श्रमिक बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी और मजबूत व्यवस्था कितनी आवश्यक है। समय रहते समस्या का समाधान कर श्रमिक परिवारों को राहत प्रदान करना प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में ईको सेंटर ताला में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम संबंधी बैठक संपन्न

ग्राम स्तर पर चौपाल लगाकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश

उमरिया।

कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में ईको सेंटर ताला में मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम एवं उसके दीर्घकालिक एवं स्थायी समाधान के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सहाय ने वन विभाग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कोर एरिया में निवासरत ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु ग्राम स्तर पर नियमित जनचौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होते ही त्वरित निर्णय लेते हुए रेस्क्यू टीम को तत्काल मौके पर भेजने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने पर बल दिया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने कोर एरिया में बाउंड्री निर्माण, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत निर्मित जल संरचनाओं के समुचित प्रबंधन, कोर क्षेत्र की स्पष्ट मार्किंग तथा बाघ से संबंधित घटनाओं के दौरान पुलिस एवं वन विभाग द्वारा आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का सुझाव दिया। उन्होंने 15वें एवं 5वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग कर आवश्यक स्थानों पर फेंसिंग कराने की बात भी कही। उप संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व योहान कटारा ने लेंटाना जैसी घनी झाड़ियों को चिन्हित कर हटाने, एनजीओ के सहयोग से सोलर लाइट स्थापित करने तथा खुले कुओं को ढंककर वन्य जीवों की दुर्घटनाजन्य मृत्यु रोकने के सुझाव दिए। वनमंडलाधिकारी विवेक सिंह ने सूखी जल संरचनाओं को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा विस्थापन के लिए चयनित ग्रामों से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण पर बल दिया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मानपुर सुश्री हरनीत कौर कलसी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की सूचना मिलते ही रेस्क्यू अमले को तत्काल घटनास्थल पर भेजने, प्रभावित परिवारों से पुलिस, वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संवेदनशीलता के साथ संवाद स्थापित करने तथा सभी मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों की संपर्क सूची अद्यतन रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कोर एवं बफर क्षेत्र के ग्रामों में जनजागरूकता चौपाल आयोजित करने तथा खुले में शौच के लिए जंगल जाने वाले परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी बताई।

तहसीलदार मानपुर ने कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर पर्याप्त पुलिस एवं वन अमले की तैनाती, उद्घोषणा हेतु माइक व्यवस्था, बैरिकेडिंग कर आवागमन नियंत्रित करने तथा फसल हानि प्रकरणों में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर एवं पदनाम अंकित करने के सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में ग्राम पंचायत झलवार के सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी अपने सुझाव रखे। बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए समन्वित एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई।

नगरीय निकाय पाली में तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का हुआ समापन
कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को वितरित किए हितलाभ

उमरिया।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आमजन को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय निकाय पाली में आयोजित तीन दिवसीय जन कल्याण शिविर का समापन कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने कहा कि जिले के सभी विकासखंडों एवं नगरीय निकायों में जन कल्याण शिविरों का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य शासन की सेवाओं एवं योजनाओं को आम नागरिकों तक सरल, सहज एवं सुलभ रूप से पहुंचाना है। शिविरों के माध्यम से 111 प्रकार की विभिन्न सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है। शिविर के दौरान कलेक्टर श्रीमती सहाय द्वारा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त पात्रता पर्ची, कल्याणी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, फौती नामांतरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, संबल कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा अनुग्रह सहायता राशि सहित विभिन्न योजनाओं के हितलाभ पात्र व्यक्तियों को वितरित किए गए। शिविर में जानकारी दी गई कि तीन दिनों के दौरान कुल 527 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 350 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि 171 आवेदन लंबित हैं। अधिकारियों ने बताया कि शेष आवेदनों का भी शीघ्र निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को समय पर लाभ एवं राहत मिल सके। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं एवं सेवाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे। कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभय सिंह ने स्टॉलों का अवलोकन कर विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति एवं लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।

राशन प्राप्त करने वाले हितग्राही 30 जून तक अनिवार्य रूप से कराएं री-ईकेवाईसी

उमरिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से प्रतिमाह निःशुल्क राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की पांच वर्ष पुरानी ई-केवाईसी को खाद्य विभाग, भोपाल द्वारा अमान्य घोषित किया गया है। जिले के 33,890 ऐसे सदस्यों को 30 जून 2026 तक पुनः बायोमेट्रिक आधार सत्यापन कराकर री-ईकेवाईसी कराना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में री-ईकेवाईसी नहीं कराने पर शासन स्तर से राशन प्राप्त करने की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

कलेक्टर श्रीमती राखी सहाय ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को जून माह के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों की पहचान को आसान बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए गए हैं।

बादल छाए तो बिजली गुल, हवा चली तो अंधेरा, जमुना-भालूमाड़ा क्षेत्र में अघोषित कटौती से जनता बेहाल

बिजली संकट से पानी की सप्लाई प्रभावित दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट

हरिभूमि न्यूज भालूमाड़ा।

आधुनिक जीवन में बिजली अब केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि दैनिक जरूरत का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इसके बावजूद पसान नगर पालिका क्षेत्र के जमुना-भालूमाड़ा सहित आसपास के दर्जनों गांवों में वर्षों से चली आ रही अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि क्षेत्र के लोगों के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि बादल छाए तो बिजली बंद, हवा चली तो सप्लाई ठप, बारिश की बूंदें गिरते ही लाइन बंद और तेज गर्मी या उमस बढ़ते ही बिजली गायब हो जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह समस्या एक-दो दिन या कुछ महीनों की नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है। हर मौसम में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों और कई बार दो से तीन दिनों तक घोषित कटौती की जाती है। इसके अलावा छोटी-छोटी तकनीकी खराबियों के कारण भी पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

30-35 वर्ष पुरानी लाइन बनी बड़ी समस्या- जानकारों के अनुसार कोतमा उपकेंद्र से भालूमाड़ा तक आने वाली बिजली सप्लाई लाइन करीब तीन दशक पुरानी है। यह लाइन जंगल, खेत, नालों और पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है, जिसके कारण तेज हवा, बारिश या प्राकृतिक परिस्थितियों में तार टूटने, जंपर खराब होने और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रहती हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से इस लाइन के व्यापक सुधार की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

पसान उपकेंद्र बनने के बाद भी नहीं मिली राहत- क्षेत्र में विद्युत समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से लगभग पांच वर्ष पूर्व पसान में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया गया था। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी है। नागरिकों का कहना है कि अधिकांश क्षेत्रों की निर्भरता आज भी पुरानी सप्लाई लाइन पर बनी हुई है, जिसके कारण बिजली संकट लगातार जारी है।

पानी की समस्या ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें- अघोषित बिजली कटौती का असर केवल रोशनी तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बोरवेल और समरसेबल पंपों पर निर्भर है। बिजली बंद होने से पंप नहीं चल पाते, जिससे लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। गर्मी और उमस के दिनों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

व्यापार और रोजगार पर भी पड़ रहा असर- बिजली आधारित छोटे उद्योग, वेल्डिंग कार्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, कंप्यूटर, फोटोकॉपी एवं अन्य व्यवसायों से जुड़े दुकानदारों का कहना है कि बार-बार होने वाली कटौती से उनका काम प्रभावित हो रहा है। महंगी दरों पर बिजली बिल जमा करने के बावजूद पर्याप्त और नियमित बिजली नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है।

शिकायत व्यवस्था और सुधार कार्यों पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली गुल होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और त्वरित समाधान पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। लोगों ने विद्युत विभाग से मांग की है कि पुरानी लाइनों के सुधार, नियमित रखरखाव और बेहतर शिकायत निवारण व्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग- क्षेत्रवासियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर जैसी योजनाओं के साथ-साथ विद्युत अधोसंरचना के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मांग की है कि जमुना-भालूमाड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की वर्षों पुरानी बिजली समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए, ताकि लोगों को अघोषित कटौती और उससे पैदा होने वाली परेशानियों से राहत मिल सके। लगातार बढ़ती इस समस्या ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा कर रहे हैं, तो उन्हें निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुविधा कब तक मिल पाएगी। क्षेत्र की जनता अब केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की प्रतीक्षा कर रही है।

खबर संक्षेप

पत्रकार से गाली गलौज मामले में अब तक दर्ज नहीं हुई एफ आई आर।

ब्यौहारी। थाना ब्यौहारी- के अंतर्गत ग्राम साखी में घटिया रोड बन रही थी जिसकी फोटो, वीडियो पत्रकार सूर्यभान यादव के द्वारा लिया गया सरपंच द्वारा जब उसकी जानकारी जनपद पंचायत के पास बैठने वाले निलेश सोनी तथा अपने को पूरे जनपद पंचायत का पंचायतों का ठेकेदार बताने बाले निलेश सोनी को दी तो वह भड़क गए और अनाप-शनाप गालियां अश्लील गालियां दी जिसकी शिकायत 12/06/26 को थाना ब्यौहारी- में की गई लेकिन पत्रकार से गाली गलौज का गंभीर मामला होते हुए भी अभी तक थाना प्रभारी द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया उनके द्वारा अपराध दर्ज करने में हीला हवाली की जा रही है पीड़ित पत्रकार ने शीघ्र फिर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किये जाने की मांग की है।

21 जून को सुबह 7 से आयोजित होगा सामूहिक योगाभ्यास

शहडोल। 12 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून 2026 को जिलेभर में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए प्रेरित करना है। जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पंचायतों, नगरीय निकायों सहित विभिन्न संस्थानों में सुबह 7 बजे से 7:45 बजे तक सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इससे पूर्व सुबह 6 बजे प्रतिभागियों की उपस्थिति, 6:30 बजे राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण तथा 6:45 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद योगाभ्यास प्रारंभ होगा। कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, पुलिस, विभिन्न विभागों, उद्योगों एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आयोजकों को योग संगम पोर्टल पर पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिले की सहभागिता राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो सके। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 21 जून की सुबह शहडोल शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक योग और स्वास्थ्य का संदेश गूंजेगा तथा बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास में शामिल होकर स्वस्थ जीवन का संकल्प लेंगे।

रेलवे मजदूर कांग्रेस ने दी विदाई और किया नवपदस्थ PCPO का स्वागत आदित्य कुमार बोले बिलासपुर जोन में कार्यकाल रहा बेहद सफल

शहडोल। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (SECR) बिलासपुर जोन में रेलवे मजदूर कांग्रेस द्वारा एक गरिमामयी विदाई सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। 18 जून को रेलवे महाप्रबंधक बिलासपुर के सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में निवर्तमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (PCPO) आदित्य कुमार को भावभीनी विदाई दी गई, साथ ही नव पदस्थ PCPO डॉ. दर्शनीयता बी अहुलवालिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

मजदूर कांग्रेस की भूमिका सराहनीयः आदित्य कुमार

समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान PCPO आदित्य कुमार ने कहाःरसाउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में मेरा कार्यकाल बहुत ही सफल रहा है। कार्मिक विभाग ने नागपुर, रायपुर और बिलासपुर मंडल में रेल कर्मचारियों के वेलफेयर, प्रमोशन और वेतन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन कार्यों को अमलीजामा पहनाने में रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर की भूमिका बेहद सकारात्मक रही। मैं अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के अध्यक्ष डी. के. स्वाइन और महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ।

कर्मचारी हित में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय

रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल कार्यकारी अध्यक्ष व मीडिया प्रभारी लक्ष्मण तथा जोनल प्रवक्ता गोपी राव ने बताया कि यह आयोजन महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में किया गया।महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण ने निवर्तमान पीसीपीओ आदित्य कुमार के सरल और संवेदनशील स्वभाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में रेल कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।नवपदस्थ पीसीपीओ का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि डॉ. अहुलवालिया के पास बेहतरीन प्रशासनिक क्षमता और इस जोन का पुराना अनुभव है, जिसका सीधा लाभ बिलासपुर जोन के रेल कर्मचारियों को मिलेगा।

समस्याओं का निराकरण बेमिसालः

समारोह में नवपदस्थ PCPO श्रीमती डॉ.दर्शनीयता बी अहुलवालिया ने बिलासपुर जोन से अपने पुराने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि वे यहाँ के तीनों मंडलों में काम कर चुकी हैं और मजदूर कांग्रेस के पदाधिकारियों से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि अनुशासन के साथ रेल प्रशासन के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को रखना और उनका निराकरण कराना मजदूर कांग्रेस की बेमिसाल खूबी है।

शाल, श्रीफल से हुआ सम्मान

समारोह के दौरान निवर्तमान PCPO आदित्य कुमार और नवपदस्थ PCPO डॉ. अहुलवालिया को मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के जोनल अध्यक्ष डी. के. स्वाइन, जोनल महामंत्री पीतांबर लक्ष्मी नारायण और रायपुर के मंडल समन्वयक बी.डी.प्रसाद द्वारा शाल, श्रीफल एवं फूलों का बुके भेंट कर सम्मानित किया गया।

ये रहे उपस्थितः

इस विदाई सह स्वागत समारोह का कुशल संचालन अर्बन बैंक के डायरेक्टर आर. के. यादव ने किया। कार्यक्रम में रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के केंद्रीय कोषाध्यक्ष सांई किरण,उपाध्यक्ष भीमराव बोदलकर सहित कई केंद्रीय पदाधिकारी और बिलासपुर के शाखा सचिव मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

जन कल्याण शिविर का मिल रहा हितग्राहियों को लाभ

नगर पालिका पाली में जन कल्याण शिविर का आयोजन

बिरसिंहपुर पाली। शासन की जन कल्याण कारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन व्दारा चलायी जा रही योजना के क्रियांवयन के परिपालन में नगर पालिका परिषद पाली में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के स्टाल लगाकर हितग्राहियों को लाभ पहुचाने का काम किया गया। पाली नगर पालिका में इस तारतम्य में तीन दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया जो की 15 जून से प्रारम्भ होकर 17 जून तक चलेंगा। बीते दिवस शिविर का शुभारम्भ नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष सुश्री शंकुतला प्रधान जी के व्दारा किया गया। प्रथम दिवस में जन कल्याण शिविर में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 65 , राजस्व विभाग से 35, महिला एवं बाल विकास से 47 , स्वास्थ्य विभाग 60 , सामाजिक न्याय एवं निशक्त जन विभाग 41,एवं सामान्य प्रशासन विभाग के 16 आवेदन पत्र दर्ज किये गए।बताया जाता है की इनमें से अधिकांश आवेदनों का स्थानीय स्तर से जिनका समाधान किया जाना था, उनका मौके पर निदान किया गया।

आज से जन-कल्याण शिविर एवं जैविक-प्राकृतिक खेती विषयक कार्यशालाओं का आयोजन

उमरिया। उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषकों के हित में जन-कल्याण शिविर एवं जैविक-प्राकृतिक खेती विषयक कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 19 जून 2026 को विकासखंड मानपुर के ग्राम डोडका तथा 20 जून 2026 को विकासखंड करकेली के ग्राम धवईझर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना तथा टिकाऊ, लाभकारी एवं पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।कार्यशालाओं में कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों, जैविक खाद एवं जीवामृत के उपयोग, बीज उपचार, कीट एवं रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं वैकल्पिक उपयोग संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं खेती की लागत कम करने के प्रभावी उपायों पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।जन-कल्याण शिविरों के दौरान किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा तथा कृषि एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा।कृषि विभाग ने जिले के कृषकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यशालाओं एवं शिविरों का लाभ प्राप्त करें तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती को अपनाकर कृषि लागत में कमी, मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ें।

विकास के दावों के बीच बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित सैकड़ों आदिवासी परिवार

उमरिया। जब पूरा देश डिजिटल इंडिया, स्मार्ट गाँव और विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब उमरिया जिले के पाली विकासखंड के घुनघुटी ग्राम पंचायत की आदिवासी बहुल गांव गाँधीग्राम, और कठई ग्राम पंचायत की चिनकी,सांस, गढकुर जैसे वनांचल आदिवासी बहुल गांवों में बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे है, जहाँ पर सूर्यास्त होते ही पूरे गाँव अंधेरे की आगोस की घनी चादर में डूब जाता है , जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो समय अभी भी अठारहवीं शताब्दी में ठहरा हुआ है।

घुनघुटी ग्राम पंचायत के सांस गाँव में लगभग तीन सौ भूमिया (भील) आदिवासी परिवार जो की बैगा प्रजाति से जुडा माना जाता है , इस गाँव के आदिवासी दिन भर खेतों में और घुनघुटी से मेहनत-मजदूरी कर जब शाम को घर लौटते हैं तब दिनभर कठिन परिश्रम करने के बाद जब ग्रामीण अपने घरौंदे में प्रवेश करते हैं, तब उनका स्वागत धुंध अंधकार के व्दारा किया जाता है, जब आज भारत इक्कीसवीं सदी के आधुनिक सुविधाओं से सूर्य की भांति जगमगाती रोशनी से होती है तब इन गांवों के आदिवासियों का अभिनंदन घोर अंधकार से होता है। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई विशेष कर प्रभावित होती है, महिलाओं को घरेलू कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है , क्योंकि आज भी ग्रामीणों का जीवन ढिबरी एवं लालटेन की सीमित रोशनी तक सिमटा हुआ है।

सबसे बड़ा दुर्भाग्य इन गांवों का यह है कि चुनावी मौसम में बरसाती नेताओं जनप्रतिनिधियों और उनके नुमाइंदों की आवाजाही तो होती है, आदिवासियों को बिजली के सब्ज बाग भी दिखाये जाते हैं, विकास के अनेक वादे परोसे जाते हैं, किन्तु चुनाव समाप्त होते ही आदिवासियों की थाली खाली की खाली रह जाती है। विदित होवे की वर्षों से ग्रामीण बिजली उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह जायज़ मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है।इसके लिए न क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद करते हैं, न इस ओर प्रशासनिक पहल होती है, जबकि बिजली अब केवल एक प्रकाश का माध्यम बची बल्कि यह एक ऐसी सुविधा बन गयी है, जो की आज जीवन के हर पहलु को प्रभावित करती है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन के साधन, दूर संचार के साथ ही आज आर्थिक विकास का आधार भी बनी हुई है। बिजली के अभाव में गाँव के बच्चे आधुनिक शिक्षा से पीछे छूट रहे हैं तथा ग्रामीण शासन की अनेक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। ऐसे में इन बिजली विहीन गाँवों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली सुविधा से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इन गाँवों के ग्रामीणों ने शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों से मार्मिक अपील की है कि उनके गाँव तक भी विकास की रोशनी पहुँचाई जाए। जिस दिन यहाँ के घरों में पहला बल्ब जलेगा, उस दिन केवल अंधेरा ही नहीं मिटेगा, बल्कि सैकड़ों आदिवासी परिवारों के सपनों को भी नया उजाला मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गाँधीग्राम की इस पीड़ा को सुनेंगे, या फिर यह गाँव आने वाले वर्षों तक भी विकास की रोशनी से वंचित रहेगा?

कृषि विभाग प्रदर्शन खेती के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने हेतु करें प्रेरितः आयुक्त

सभी विभाग वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाकर करें कार्य

शहडोल। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन विभागों की संभाग स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कृषि विभाग प्रदर्शन खेती के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने हेतु प्रेरित करें। किसानों को प्रदर्शन वालें खेतों में ले जाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में हुई वृद्धि तथा इन प्रदर्शनों में उत्पादन बढ़ाने हेतु किए जाने वाले नवाचारों के संबंध में किसानों को अवगत कराएं। उन्होंने शहडोल संभाग में श्रीअन्न कोदो कुटकी तथा दलहन एवं तिलहन का रकवा बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास मुद्रिका सिंह, संयुक्त संचालक कृषि जेएस पेन्द्राम, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. पंकज सिंह सहित संभाग के तीनों जिलों के उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, सहायक संचालक उद्यानिकी, सहायक संचालक मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी, बीज निगम, एमपीएग्रो कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. केपी तिवारी, डॉ. बीके प्रजापति, डॉ. धनन्जय सिंह, सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुक्त श्रीमती गुप्ता ने कहा कि संभाग में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन हेतु बनाए गए क्लस्टरों का संबंधित अधिकारी नियमित भ्रमण करें। किसानों को प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभों की जानकारी दें तथा उत्पादन की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग हेतु प्रोत्साहित करें। शासन द्वारा प्राप्त नए क्लस्टर निर्माण के लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा करें। ड्रिप एरिगेशन तथा प्रेसराईज्ड एरिगेशन कर रकवा बढ़ाएं। नरवाई प्रबंधन हेतु किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान तथा भूसा बनाने एवं स्ट्रीपर के माध्यम से सीधी जुताई के लाभों से अवगत कराएं।

उन्होनें कहा कि खेत की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक का उपयोग करने हेतु मृदा परीक्षण कराएं तथा किसानों को खेत की आवश्यकता के अनुसार उर्वरक के उपयोग की जानकारी दें। इस अवसर पर उन्होंने संभाग के तीनों जिलों में कृषि के क्षेत्र में किए जाने वाले नवाचारों की भी जानकारी ली। संयुक्त संचालक कृषि द्वारा बताया गया कि संभाग में तिल, रामतिल तथा मूंगफली का रकवा बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही चियासीड तथा धान के साथ मत्स्यपालन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने कहा कि सभी सहकारी समितियों में उर्वरक एवं बीज का पर्याप्त भण्डारण कर लिया जाए। अभियान चलाकर सहकारिता सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए संभाग में फलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आम, अमरूद, ड्रेगन फूड, मुनगा, नाशपाती आदि फलदार पौधों का रोपण किया जाए। पर ड्राप-मोर क्राप के तहत सप्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जाए।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हिरण्यगर्भा योजना तथा क्षीरधारा ग्राम योजना के तहत पशु नश्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान, शत-प्रतिशत पशुओं की टैगिंग, टीकाकरण का अभियान चलाया जाए। गौशालाओं में अच्छी गायों का चयन कर सेक्स सार्टेड सीमेन्स से गर्भाधान किया जाए। किसानों को टीकाकरण कराने पालतू पशुओं के नश्ल सुधार, दुधारू पशुओं के पोषण आहार, पशुओं के अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। इस अवसर पर उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की समीक्षा करते हुए बैंकों में प्रेषित प्रकरणों के स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग की समीक्षा करते हुए मत्स्यपालन का रकवा बढ़ाने, मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने तथा मत्स्यबीज का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने हेतु केज कल्चर को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

आमजन शासकीय योजनाओ का उठाएं लाभ: मनीषा

विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को किया हितलाभ का वितरण

सोहागपुर जनपद कार्यालय में आयोजित हुआ जन कल्याण शिविर, समस्याओं के त्वरित निराकरण के दिए गए निर्देश

शहडोल। जिले की जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों में संचालित जन कल्याण शिविरों के माध्यम से आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा हैं। इन शिविरों में विभागीय अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याएं एवं आवेदन प्राप्त कर उनका यथासंभव त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जनपद पंचायत कार्यालय सोहागपुर में विधायक श्रीमती मनीषा सिंह की उपस्थिति में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं आवेदन प्रस्तुत किए।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती मनीषा सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए विकास एवं जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्तियों तक केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहे।विधायक ने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में जन कल्याण शिविरों में पहुंचकर पात्रतानुसार विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ उठाकर नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। विधायक ने लाडली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान कार्ड, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। शिविर के दौरान आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित निराकरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई भी की गई। इस अवसर पर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष शक्ति सिंह चंदेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गलैक्सी नागपुरे अन्य जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

लोक सेवा गारण्टी के तहत चिन्हित सेवाएं आवेदकों को समय-सीमा में देना सुनिश्चित करें: कलेक्टर

नामान्तरण, सीमांकन, आरबीसी तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समय-सीमा की बैठक में लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय-सीमा के भीतर चिन्हित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्राकृतिक प्रकोप वन्य प्राणियों से फसलों को होने वाली हानि के प्रकरणों, अविवादित नामांतरण, सीमांकन प्रकरणों तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हुए न्यायालय को अवगत कराया जाए। संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, श्रीमती मिनीषा पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अन्तोनिआ एक्का, सुश्री अर्चना मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

पशुपालकों के लिए संजीवनी बनी 1962 मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, घर बैठे मिलेगा पशुओं को उपचार

अनूपपुर। जिले के पशुपालकों के लिए पशुधन संजीवनी योजना के तहत संचालित चलित पशु चिकित्सा इकाई (मोबाइल एम्बुलेंस) वरदान साबित हो रही है। इस सेवा के जरिए अब बीमार पशुओं को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि डॉक्टर खुद पशुपालक के घर पहुँच रहे हैं। योजना के तहत एम्बुलेंस में तैनात पशु चिकित्सक और सहायक, आवश्यक दवाओं और आधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुँचते हैं। इस सेवा के माध्यम से बीमार पशुओं के इलाज के साथ-साथ मौके पर ही टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं भी दी जा रही हैं। इस घर पहुँच सेवा का लाभ उठाने के लिए पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करना होता है। कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज होते ही जीपीएस के माध्यम से नजदीकी एम्बुलेंस को पशुपालक के घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। यह सेवा प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक चालू रहती है। शासन द्वारा इस आपातकालीन सेवा के लिए बहुत ही नाममात्र का शुल्क तय किया गया है। योजना के अंतर्गत गाय और भैंस के सभी प्रकार के उपचार व सेवाओं के लिए 150 रुपये तथा कुत्ते व बिल्ली के इलाज के लिए 300 रुपये का शुल्क निर्धारित है। पशु चिकित्सा विभाग ने जिले के सभी किसानों और पशुपालकों से अपील की है कि पशुओं के बीमार होने पर बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1962 पर सूचना दें, ताकि समय पर एम्बुलेंस बुलाकर पशुधन की रक्षा की जा सके।

मैकल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम

अमरकंटक। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आगामी 21 जून को पवित्र नगरी अमरकंटक स्थित मैकल पार्क में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होकर 7:45 बजे तक संचालित होगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए कलेक्टर हर्षल पंचोली ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ वसीम भट्ट को नोडल अधिकारी तथा जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक उमेश पाण्डेय को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा स्वस्थ एवं निरोग जीवन के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की है। योग दिवस का यह आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामूहिक सहभागिता का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अनूपपुर और जैतहरी में आयोजित होंगी कार्यशालाएं

अनूपपुर। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) तक संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि विकास एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यशालाएं 19 जून को प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत जमुड़ी में तथा 20 जून को प्रातः 11 बजे जनपद पंचायत अनूपपुर की ग्राम पंचायत दारसागर में आयोजित की जाएंगी।

एसपी की ओवरलोड परिवहन पर सख्ती, 42 ट्रकों में ओवरलोडिंग, कार्रवाई सिर्फ चार तक सीमित

रेलवे रैक प्वाइंट तक भेजे जा रहे चावल में क्षमता से अधिक लोडिंग, चार वाहनों पर जुर्माना

अनूपपुर। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के हजारों क्विंटल चावल के परिवहन में ओवरलोडिंग का मामला सामने आने के बाद अनूपपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराव के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने दो ट्रको पर कार्यवाही की तो वहीं यातायात पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ दो ट्रको पर 41 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार अनूपपुर जिले से मुरैना जिले के लिए भेजे जा रहे चावल को रेलवे रैक प्वाइंट तक पहुंचाने के लिए लगाए गए कई ट्रकों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लादा जा रहा था। शिकायतों और निगरानी के दौरान ओवरलोड परिवहन की पुष्टि होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार ट्रकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना लगाया। जांच और चेकिंग के दौरान कई ट्रकों के चालक अपने वाहन मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। जिससे ट्रको पर कार्यवाही ना हो सके। रेलवे रैक प्वाइंट तक चावल पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में ओवरलोडिंग न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, बल्कि परिवहन नियमों का भी खुला उल्लंघन है।

कोतवाली पुलिस ने दो ट्रको पर की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए क्षमता से अधिक लदे दो ट्रकों को पकड़ा है। कार्रवाई कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद जैन के नेतृत्व में 17 जुन को की गई। जांच के दौरान ट्रक क्रमांक एमपी 20 एचबी 5660 एवं एचपी 38 जे 4533 में निर्धारित क्षमता से अधिक चावल लोड पाया गया। ओवरलोडिंग की पुष्टि होने पर दोनों वाहनों को थाना परिसर लाया गया और वैधानिक कार्रवाई की गई। मामले में ट्रक चालक राजेश यादव पिता रामसुरत यादव 40 वर्ष निवासी चंदिया तथा दीपेश यादव पिता सुखसेन प्रसाद यादव 30 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी कला थाना ब्यौहारी के विरुद्ध धारा 113/194(1) के तहत ओवरलोडिंग तथा परमिट की शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर धारा 66/192(ए) मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

यातायात की कार्यवाही बना दिखावा

17 जून को पुलिस अधीक्षक ने यातायात और कोतवाली पुलिस को चावल से लदे ओव्हर लोड़ ट्रको पर कार्यवाही के निर्देश दिये। जहां कोतवाली पुलिस ने तत्काल ओव्हर लोड़ दो ट्रको पर कार्यवाही की गई। लेकिन यातायात पुलिस इस कार्यवाही बचती देखी गई। वहीं कोतवाली पुलिस की कार्यवाही के दूसरे दिन यातायात पुलिस मौके पर पहुंचकर 5 ट्रको की जांच की गई, जिसमें तीन ट्रक अंडरलोड पाई गई। वहीं दो ट्रक जिनमें एमपी 09 एएल 9933 पर 20 हजार एवं एमपी 21 एच 6333 पर 21 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि 17 जून को जिले के बीओटी गोदाम दारसागर, रामजानकी वेयर हाउस, श्री शिवाय वेयर हाउस एवं अन्नपूर्णा वेयर हाउस से 17 जून चावल से लदे लगभग 42 ट्रक ओव्हर लोड़ निकले थे, जिनमें दिन रात सड़को पर खड़े रहने वाली यातायात पुलिस ने सिर्फ 2 ट्रक ही ओव्हर लोड़ मिले।

यातायात को 42 ट्रको में सिर्फ 2 ट्रक ओव्हर लोड़ मिले

रेलवे रैक प्वाइंट के लिये जिले के चार गोदामों से 17 जून को निकले 42 ओव्हर लोड़ ट्रको में यातायात को सिर्फ 2 ट्रक ओव्हर लोड़ मिले। जबकि यातायात पुलिस इन दिनों दिन रात दो दो प्वांइट बनाकर हाइवे में खड़े होकर यातायात नियमों के उल्लंघनन करने वाले वाहनों पर कार्यवाही की जा रही है। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार बीओटी गोदाम दारसागर से चावल के 20 ट्रक, रामजानकी वेयर हाउस से 12, श्री शिवाय वेयर हाउस से 3 एवं अन्नपूर्णा वेयर हाउस से 7 ओव्हर लोड़ ट्रक निकले थे। एसपी के कड़े रूख अपनाने के बाद कई ओव्हर लोड़ ट्रक तुलसी वेयर हाउस मेड़यिारास में कार्यवाही होने से बचने के लिये खड़ी हो गई। इतना ही नही गायत्री ट्रांसपोर्टर द्वारा एक एक कर ट्रको को वेयर हाउस से बाहर निकालते हुये रेलवे रैक प्वांइट पहुंचाई जा रही है। वहीं 18 जून को लोड़ हुये सभी ट्रक अंडर लोड़ कर दिये गये है।

एसपी की कार्यवाही देख अंडर लोडिंग हुआ चालू

पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देशन और कड़ी निगरानी के बाद 18 जून को चारो वेयर हाउस से चावल अंडर लोड़ दिया जाने लगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये यातायात नियमों के अनुरूप से वाहनों में क्षमता से अधिक माल परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। वहीं जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 17 जून को कलेक्टर हर्षल पंचोली की उपस्थिति में में भी ओवरलोड वाहनों के बढ़ते संचालन को गंभीरता से लेते ऐसे वाहनों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गये थे। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है।

अमरकंटक में युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, चुनाव आयोग एवं धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन

अमरकंटक। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष यश लखन घनघोरिया, पुष्पराजगढ़ विधायक फुन्देलाल सिंह मार्को के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस अमरकंटक द्वारा चुनाव आयोग एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानवेंद्र मिश्रा एवं आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को की अनुशंसा पर किया गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पुष्पराजगढ़ विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बिरू तंबोली ने किया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों, युवाओं एवं छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए युवाओं के हितों की रक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की मांग की। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि श्यामलाल सेन, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हरि सिंह उइके, नगर कांग्रेस अध्यक्ष शितेश सारीवान, लखन झारिया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं युवा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता खिलेश्वर दुबे, रवि शंकर परस्ते, मनीष प्रधान, राजेश नागवंशी सहित बड़ी संख्या में युवा साथी कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संगठन युवाओं, छात्रों, आदिवासियों एवं आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा।

वन डिपो के पास बुधवार की देर शाम घटित हो गया सड़क हादसा

वाहन चालक को आई गंभीर चोट, शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर

कोतमा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 मे वन डिपो के पास बुधवार की देर शाम सड़क हादसा घटित हो गया बताया जाता है कि कोतमा से मनेन्द्रगढ़ की ओर जा रही बोलेरो वाहन को ट्रेलर वाहन ने पीछे से टक्कर मार दिया। दुर्घटना में बोलेरों वाहन चालक को गंभीर चोट आई है। घायल को गंभीर हालत मे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए शहडोल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया।

घटना की जानकारी लगते ही कोतमा पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुटी गई। पुलिस ने बताया कि बोलेरो वाहन अनुपपुर से मनेंद्रगढ जा रही रही थी जिसमें आशुतोष कुमार वाहन चला रहे थे साथ मे उनके भाई मणिवेश सिंह दोनों निवासी सीतापुर एवं बदरा से सूर्य भान को साथ ले जा रहे थे तभी वन डिपो के पास हाइवा वाहन का चालक तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से बोलेरो वाहन को टक्कर मार कर भाग गया बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि हाइवा वाहन का चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए भाग रहा था तभी बसखली तिराहा के पहले हाइवा का टायर निकल कर दूर फेका गया और चालक मौके से भाग गया। बताया जाता है कि हाइवा वाहन बुढार के गणपत लाल के अंडर मे चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हाइवा वाहन को थाना मे खड़ा करवाते हुए चालक की तलाश कर रही है।

ग्राम पंचायत हर्राटोला में विकास के नाम पर खेल?

लाखों की वित्तीय अनियमितता और घटिया निर्माण के आरोप, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

जिले की ग्राम पंचायत हर्राटोला में विकास कार्यों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव एवं सरपंच पति पर ग्राम सभा की सहमति के बिना निर्माण कार्य कराने, वित्तीय अनियमितता, फर्जी बिलों के जरिए राशि आहरित करने तथा घटिया निर्माण सामग्री उपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने एसडीएम पुष्पराजगढ़ सहित जिला पंचायत सीईओ को शिकायत सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। मामले ने पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

अनूपपुर। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत हर्राटोला इन दिनों भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोपों को लेकर चर्चा में है। ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत में वर्ष 2024 से अब तक किए गए कई विकास कार्यों में नियमों की अनदेखी कर लाखों रुपये का आहरण किया गया है। शिकायत के अनुसार ग्राम सभा की स्वीकृति और आम सहमति के बिना सड़क एवं पुल निर्माण कार्य कराए गए है, वहीं कई कार्यों में वास्तविक लागत से कहीं अधिक राशि निकाल ली गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और गिट्टी-बोल्डर की जगह मिट्टी व घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, गांव के लोगों ने सामूहिक सहमति पत्र देकर कुछ निर्माण कार्यों का विरोध भी दर्ज कराया है। अब ग्रामीणों की मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए तथा निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

ग्राम सभा को दरकिनार कर हुए विकास कार्य

ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में कई निर्माण कार्य ग्राम सभा की अनुमति और ग्रामीणों की सहमति के बिना शुरू कर दिए गए है। शिकायत में कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने जनता की राय लेने के बजाय मनमाने तरीके से योजनाओं का चयन किया और कार्यों को स्वीकृत कराया है। इससे गांव में असंतोष का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनभागीदारी है, लेकिन यहां निर्णय कुछ लोगों तक सीमित होकर रह गए हैं। लोगों ने प्रशासन से ग्राम सभा के रिकॉर्ड और प्रस्तावों की जांच कराने की मांग की है।

सड़क निर्माण में लाखों की अतिरिक्त राशि निकालने का आरोप

शिकायत पत्र में दो सड़क निर्माण कार्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार हर्राटोला में लगभग दो लाख रुपये लागत वाले कार्य में पांच लाख रुपये अतिरिक्त आहरित किए गए, जबकि सोनियामार क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपये की लागत वाले कार्य के बदले करीब चार लाख रुपये अतिरिक्त निकाले जाने का आरोप है। ग्रामीणों का दावा है कि वास्तविक कार्य और भुगतान में बड़ा अंतर है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह पंचायत निधि के दुरुपयोग का गंभीर मामला हो सकता है। ग्रामीणों ने भुगतान संबंधी सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।

पुल निर्माण को लेकर भी उठे सवाल

ग्राम पथरी टोला में नदी किनारे बनाए जा रहे पुल को लेकर भी विवाद गहरा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर पुल बनाया जा रहा है, वहां इसकी आवश्यकता नहीं है। शिकायत में उल्लेख है कि गांव की सामूहिक बैठक में इस निर्माण का विरोध किया गया था, इसके बावजूद कार्य जारी रखा गया। लोगों का आरोप है कि जनता की जरूरतों की बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि पुल निर्माण की वास्तविक आवश्यकता है तो उसका तकनीकी परीक्षण और सामाजिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए।

घटिया निर्माण सामग्री से गुणवत्ता पर सवाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया। शिकायत में कहा गया है कि पुल और सड़क निर्माण में गिट्टी और बोल्डर की पर्याप्त मात्रा नहीं डाली गई, जबकि मिट्टी और अन्य कम गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया गया। इससे निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में ऐसे निर्माण कार्य जल्दी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और लोगों की जान-माल के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए तकनीकी जांच कर गुणवत्ता की पुष्टि की जानी चाहिए।

ग्रामीणों ने मांगी उच्चस्तरीय जांच, कार्रवाई की मांग

मामले को लेकर ग्रामीण अब खुलकर सामने आ गए हैं। सामूहिक हस्ताक्षरों के साथ सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने पूरे पंचायत कार्यकाल के विकास कार्यों, भुगतान रिकॉर्ड, मस्टर रोल और निर्माण गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी इस शिकायत को गंभीरता से देखा जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन क्या कदम उठाता है।

नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मान समारोह को सफल बनाने में जुटी आदिवासी कांग्रेस

संगठन विस्तार और जनहित के संकल्प को मिलेगी नई दिशा

अनूपपुर। मध्यप्रदेश आदिवासी कांग्रेस जिला इकाई अनूपपुर द्वारा संगठन को और अधिक मजबूत एवं जन-जन तक कांग्रेस की रीति-नीति पहुंचाने के उद्देश्य से नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मान समारोह का आयोजन 22 जून सोमवार को प्रातः 11:30 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन अनूपपुर में किया जाएगा। जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष सिंह मार्को द्वारा जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, राष्ट्रीय समन्वयक के. राजू तथा प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम की अनुशंसा पर जिले की कोतमा, अनूपपुर एवं पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इन्हीं नवनियुक्त पदाधिकारियों के सम्मान एवं मार्गदर्शन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। समारोह में पूर्व विधायक अजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह, पूर्व विधायक मनोज कुमार अग्रवाल सहित कांग्रेस संगठन एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। आदिवासी कांग्रेस ने कहा है कि संगठन की मजबूती, आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा तथा कांग्रेस की जनकल्याणकारी विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में संगठन के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कांग्रेसजन बड़ी संख्या में शामिल होकर नवदायित्व प्राप्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करेंगे। जिला आदिवासी कांग्रेस ने सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर संगठन को मजबूत बनाने और कांग्रेस की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के संकल्प को सशक्त करने का आह्वान किया है।